the banks in collusion with the Custodians or otherwise because all the items of assets etc. in which secret reserves have been accommodated, form part of the undertaking of the erstwhile banks taken over by the nationalised banks.

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण देने के लिये बंधक-पत्र का भरा जाना

*1257. **श्री हुक्म चन्द कछवाय :**
श्री अ० सिंह सहगल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्रीमती मिनीमाता अगम दासगुरु:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को ऋण देने के लिये, जीवन बीमा निगम ने केवल पत्र भरने पर जोर दिया है जब कि राज्य सरकार गारन्टी देने के लिये तैयार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बिजली उत्पादन करने के लागत में वृद्धि होगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्यप्रदेश बिजली बोर्ड को बन्धक पत्र में भरने की छूट देने का है ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री और पूर्ति राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर): (क) जी हाँ। राज्य विद्युत बोर्डों को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण अपनी बन्धक योजना के अन्तर्गत ही दिये जाते हैं।

(ख) इसके कारण, विद्युत उत्पादन की लागत वृद्धि नगण्य होती है, क्योंकि बन्धक पत्र में लगने वाला व्यय ऋण की बीस वर्ष की अवधि में बँट जाता है, और स्वीकृत ऋण की रकम की तुलना में तुच्छ होता है।

(ग) जी, नहीं।

करों की चोरी तथा तस्करी के आरोप में सजा पाये व्यक्तियों की सूची

*1258. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उन लोगों की सूची बना रखी है जिनको करों की चोरी तथा तस्करी के आरोपों में सजा हो चुकी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उस सूची को राजनैतिक दलों में वितरित करने का है जिससे ये लोग राजनैतिक दलों के साथ सम्बन्ध स्थापित न कर सकें ; और

(ग) उन राजनैतिक दलों की संख्या कितनी है जिनके सदस्यों का ऐसे सजा पाये गये व्यक्तियों के साथ संबंध हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जो व्यक्ति कर-अपवंचन अथवा तस्कर व्यापारों के आरोपों में न्यायालय से सजा पाते हैं, उनका रिकार्ड सरकार के संबन्धित विभाग अपने सामान्य कार्य के सिलसिले में रखते हैं।

(ख) कर-अपवंचन अथवा तस्कर व्यापार के आरोपों में सजा पाने वाले व्यक्तियों के नामों की सूचियों को राजनीतिक दलों में वितरित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जिन व्यक्तियों पर राजस्व अधिकारियों द्वारा, कर-अपवंचन अथवा तस्कर व्यापार के आरोप लगाये जाते हैं, उनके राजनीतिक संबंधों की तहकीकात करना राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी में शामिल नहीं है और ऐसा करना उनके कार्य के लिये आवश्यक भी नहीं है।